

शनिवार 2 फरवरी 2019

कोलकाता, चंडीगढ़,
नई दिल्ली, पटना, भोपाल,
मुंबई, रायपुर और लखनऊ
से प्रकाशित।

डॉलर रु. 71. 30 ▲ 20 पैसे | यूरो रु. 81. 70 (अपरिवर्तित) |
सोना (10ग्राम) रु. 33250 ▲ 75 रुपये | सेंसेक्स 36469.
40 ▲ 212. 70 | निफ्टी 10893. 70 ▲ 62. 70 | निफ्टी पयूचर्स
10914. 10 ▲ 20. 40 | बैंट कूड 60.50 डॉलर ▼ 0. 40 डॉलर

www.bshindi.com

बजट में क्या रहा खास

मानक कटौती की सीमा

40,000 रुपये से बढ़ाकर

50,000 करने का प्रस्ताव

किराये पर टीडीएस की सीमा

1.80 लाख से बढ़ाकर 2.40

लाख रुपये करने का प्रस्ताव

ब्याज आय पर टीडीएस कटौती

की सीमा सालाना 10 हजार

रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये

तक करने का प्रस्ताव

अगले दशक के लिए 10 सूत्री

परिकल्पना की गई पेश

भारत को 5 साल में 5,000

अरब डॉलर, 8 साल में

10,000 अरब डॉलर की

अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़

रुपये पूंजीगत व्यय का

प्रावधान, यात्री किराये, माल

भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं,

2019-20 में रक्षा बजट 3 लाख

करोड़ रुपये से अधिक

जीएसटी के तहत औसत

मासिक कर संग्रह पिछले वित्त

वर्ष के 89,700 करोड़ रुपये से

बढ़कर चालू वित्त वर्ष में रहा

97,100 करोड़ रुपये

कृत्रिम मेधा पर चलेगा राष्ट्रीय

कार्यक्रम, 1 लाख डिजिटल गांव

बनाने का लक्ष्य

शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन

93,847.64 करोड़ रुपये,

पिछले बजट आवंटन से 10

प्रतिशत अधिक

मनरेगा के लिए 2019-20 में

60,000 करोड़ रुपये आवंटित

करने का प्रस्ताव

पशु एवं मत्स्य पालन के

लिए केसीसी का विस्तार, कर्ज

पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता

अंदर के पृष्ठों पर	
बजट और सरकार/ अर्थव्यवस्था.....	पृष्ठ 2
बजट और बाजार	पृष्ठ 3
बजट और चुनाव.....	पृष्ठ 4,5
बजट और कंपनियाँ..	पृष्ठ 6
बजट विश्लेषण.....	पृष्ठ 7
बजट और जिस.....	पृष्ठ 8
बजट आयाम.....	पृष्ठ 16

व्यापार गोष्ठी

बेरोजगारी की
समस्या का स्थायी
समाधान ?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे
पले के साथ हमें इस पले पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस , 4
बहादुरशाह ज़ाफर मार्ग, नई दिल्ली-
110002 फ़ैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gushthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर
भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या सबकी उम्मीदों पर
खरा उतरा बजट

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी
कर सकते हैं। यदि आपका जवाब
हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो
BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या चंदा कोछड़
के सभी मामलों
की हो गहराई
से जांच

हां
65.00%
नहीं
35.00%

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

चुनावी पथ पर उतरा बजट

आम चुनाव से ठीक पहले मध्य वर्ग एवं किसानों को साधने में जुटी मोदी सरकार

बीएस संवाददाता

नई दिल्ली, 1 फरवरी

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में आज जब अपना पिटारा खोला तो वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट उम्मीदों के मुताबिक ही निकला। पहले ही माना जा रहा था कि आम चुनावों से ऐन पहले का यह बजट चुनावी रंग में रंगा होगा और गोयल ने बजट के जरिये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को दोबारा सत्ता की चाबी दिलाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी।

अब तक तो यही रीत रही है कि चुनावों से ऐन पहले कोई भी सरकार कराधान या व्यय के मोर्चे पर ऐसे बड़े प्रस्ताव नहीं लाती है, जो बाद में पूर्ण बजट लाने वाली नई सरकार के हाथ बांध दें, लेकिन गोयल ने अलग राह पकड़ी। उनका बजट भाषण मतदाताओं के विभिन्न वर्गों के लिए तोहफों और नेमतों के वायदों से भरा



फोटो: संजय शर्मा

पड़ा था।

गोयल ने छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपये का आय समर्थन दिए जाने की घोषणा की और इस योजना को चालू वित्त वर्ष में ही शुरू करने की बात भी कही। दूसरा बड़ा ऐलान वेतनभोगियों के लिए आया और 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय

वाले मध्य वर्ग को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन योजना में शामिल करना भी सरकार का लोकलुभावन प्रस्ताव है। तोहफों की बौछार और राजकोषीय घाटे पर लगाम एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए गोयल ने भी खजाने पर सरकार की मजबूत पकड़ को

ढीला होने दिया। यह लगातार दूसरा साल होगा, जब राजकोषीय घाटे को काबू में रखने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने कहा कि 2018-19 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 फीसदी के बराबर रहेगा, जबकि इसे 3.3 फीसदी रखने का लक्ष्य था। अगले वित्त वर्ष में भी घाटा जीडीपी के 3.4 फीसदी पर ही रहने का अनुमान लगाया गया है। अलबत्ता गोयल ने घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी पर बांधने का सरकार का संकल्प दोहराते हुए कहा कि 2020-21 तक यह मुकाम हासिल कर लिया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में केंद्र की हिस्सेदारी 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में 1 लाख करोड़ रुपये कम रहने की आशंका है, लेकिन 2019-20 में हिस्सेदारी 20 फीसदी से अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 4.47 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी की जरूरत बताई गई है, जो आर्थिक बजट अनुमान में 4.07 लाख करोड़ रुपये ही थी। इस वजह से बॉन्ड प्रतिफल में आज इजाफा देखा गया।

■ शेष पृष्ठ 4 पर

किसान, मध्य वर्ग पर मेहरबान

प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि

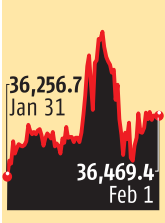
छोटे किसानों के लिए योजना शुरू होगी, जिसमें 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे। योजना इसी वित्त वर्ष से लागू होगी। चालू वित्त वर्ष के लिए इस मद में 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगले वित्त वर्ष के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा।

मझोले तबके
को कर राहत

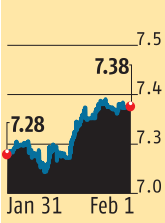
5 लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले लोगों को नहीं देना होगा कर। 6.5 लाख रुपये तक आय होने पर निवेश के जरिये मिल जाएगी आय कर से छूट

सेंसेक्स की चाल

बीएसई सेंसेक्स



प्रतिभूति (10 साल)



मामूली घाटा

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा रहेगा 3.4 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2019-20 में भी राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत पर सीमित करने का लक्ष्य



नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री

अंतरिम बजट में प्रत्येक व्यक्ति और समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद देश तेजी से संपन्न होने की राह पर बढ़ेगा और अंतरिम बजट उसकी एक झलक है

सवाल-जवाब

पीयूष गोयल,
कार्यवाहक वित्त मंत्री

‘बेहतर रहे हैं हम’

आपने कहा है कि आगामी बजट में आप आयकर दरों और स्लैब पर पुनर्विचार करेंगे? यह काम तब के वित्त मंत्री करेंगे। अंतरिम बजट में मेरे हाथ बंधे रहे हैं। लेकिन छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए पूर्ण बजट तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। इसीलिए वह राहत मैंने दे दी है। बाकी बातों पर जुलाई, 2019 में वित्त मंत्रालय संभालने वाले मंत्री फैसला करेंगे। बहरहाल पांच साल में हमने करदाताओं को कई तरह के फायदे दिए हैं।

अगर किसी की कर योग्य आय 8 लाख रुपये है तो क्या उसे मौजूदा स्लैब के मुताबिक ही कर लाभ मिलेगा? बिल्कुल। अंतरिम बजट की परिपाटी का ध्यान रखते हुए मैंने टैक्स स्लैब को हाथ नहीं लगाया है और पुराने स्लैब ही चालू रहेंगे। अंतरिम बजट की घोषणा 5 लाख रुपये से कम कर योग्य आय वाले लोगों के लिए ही है।

क्या आपने नया राजकोषीय खाका बना लिया है? सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पहले जारी आंकड़ों में आर्थिक वृद्धि का बड़ा हिस्सा दिखाई नहीं दिया क्योंकि राष्ट्र औपचारिक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है और साथ ही कर आधार तथा राजस्व में भी इजाफा हो रहा है। यह वृद्धि जीडीपी की गणना में शायद कुछ समय बाद दिखेगी। चूंकि गणना सुधरती जा रही है और नए आंकड़े कुछ समय पहले ही आए हैं, इसलिए राजकोषीय मजबूती में बहुत अंतर नहीं आया होगा। जब हम नए अनुमानों के साथ गणना करते हैं तो पता चलता है कि असली खाके

से बेहतर काम हम कर गए हैं।

राजकोषीय घाटे के संशोधित आंकड़ों पर आपकी राय? आप इस बात की तारीफ करेंगे कि इस सरकार ने लगातार चार साल तक बजट में दिए गए लक्ष्य पूरे किए हैं। हमारे वास्तविक आंकड़े संशोधित अनुमानों के बेहद करीब हैं। वास्तव में घाटा 3.36 फीसदी पर रहा है, जो 3.3 फीसदी हो सकता था। हमने बजट प्रक्रिया की शुचितता को बरकरार रखा है और वास्तविक आंकड़े ही दिखाए हैं। बजट निर्माण में ईमानदारी बरतना ही इस सरकार की राजकोषीय मजबूती रही है।

संशोधित अनुमानों में आपने उर्वरक व पेट्रोलियम सब्सिडी का पूरा इंतजाम रखा है? हमने जरूरत के मुताबिक सब किया है। वास्तव में बिना चुकाई गई सब्सिडी का जो बोझ हमें 2014 में मिला था, वह राजकोषीय अनुशासनहीता का सबसे बुरा उदाहरण था। संप्रग सरकार ने करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी नहीं चुकाई थी, जिसे इस सरकार ने चुकाया।

क्या किसानों को आय समर्थन योजना और सब्सिडी साथ-साथ जारी रहेंगी? आय सहायता योजना का सब्सिडी से लेना-देना नहीं है। पिछले कुछ अरसे में जमीनें लगातार बंटती गई हैं। 7 करोड़ से भी अधिक किसानों के पास आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन बची है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6,000 रुपये के आय समर्थन की यह योजना गांवों में रहने वाले किसानों की जिंदगियों पर कितना अधिक प्रभाव डालेगी।



कुल मिलाकर यह ' पहले खपत ' वाला बजट है जो एफएमसीजी क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित गति देगा। इससे एक बार फिर यह बात साबित होती है कि सरकार के विकासोन्मुखी और सुधारवादी एजेंडे के केंद्र में आम आदमी है

विवेक गंभीर

प्रबंध निदेशक, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स



यह भविष्योन्मुखी बजट है और इससे उपभोक्ता के हाथ में नकदी बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू उपकरणों पर जीएसटी दर में हाल की कटौती के बाद की गई इन घोषणाओं से इस क्षेत्र में मांग बढ़ने की संभावना है

सुनील डिसूजा

प्रबंध निदेशक, व्हर्लपूल इंडिया



इसमें स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर पाटना चाहती है। इन प्रयासों में हेल्थकेयर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए

संगीता रेड्डी

संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप

2 अंतरिम बजट और अर्थव्यवस्था 2019-20

► बजट प्रभाव

मध्य वर्ग को कर छूट की राहत का सकारात्मक असर उपभोक्ता बाजार के अलावा वाहन क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है। इससे खास तौर से ग्रामीण इलाके में एफएमसीजी व वाहन कंपनियों की बिक्री में और बढ़ोतरी होगी।



“ 5 लाख रुपये तक की आय पर पूर्ण कर छूट का देश का उभरता मध्य वर्ग निश्चित तौर पर स्वागत करेगा। हमारा मानना है कि यह बढ़ते मध्य वर्ग की खरीद ताकत को और मजबूत बनाएगा

रजनीश कुमार,चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूकी सरकार



राजकोषीय घाटा

2020 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीटीपी का 3.4 प्रतिशत रखा गया

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बदलकर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत कर दिया है, जबकि बजट में 3.3 प्रतिशत घाटे का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 3.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। इस तरह से अब राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत पर लाने के राजकोषीय समेकन की राह और लंबी हो गई है। गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में कृषि क्षेत्र की आमदनी बढ़ाने के लिए घोषित पैकेज को इस राजकोषीय चूक की वजह बताया है। गोयल ने कहा, ‘हम वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत बरकरार रखने की कवायद की और वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे पर काबू पाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। बहरहाल किसानों की आमदनी बढ़ाने की जरूरत पर विचार करते हुए हमने 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमान में किसानों को 20,000 करोड़ रुपये और 2019-20 के बजट अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये मुहैया कराया है।’ कम मुनाफा मिलने और कीमतों में गिरावट की वजह से किसानों की नाराजगी बढ़ने पर 2019 के आम चुनाव में सत्तासीन दल को नुकसान की संभावना है। सरकार ने इसे देखते हुए सभी छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने की घोषणा की है, जिससे उनकी निवेश जरूरतें पूरी हो सकें। कुल मिलाकर देखें तो वित्त वर्ष 2018019 के लिए राजकोषीय घाटा 6.24 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.34 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे 10,122 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल गए हैं। 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा बढ़कर 7.04 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपये की कमी और ज्यादा व्यय की प्रतिबद्धताओं की वजह से सरकार को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बढ़ाना पड़ा है। ज्यादा राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण ज्यादा शुद्ध बाजार उधारी से किया जाएगा। बजट के बाद के संवाददाता

सम्मेलन में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र की शुद्ध उधारी पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में 32,500 करोड़ रुपये ज्यादा होगी।

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने कहा, ‘पुनरीक्षित राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत बाजार के उम्मीदों के अनुरूप है। बाजार और ज्यादा चूक की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इस साल ज्यादा व्यय प्रतिबद्धताएं थीं। इस तरह से यह चूक तार्किक सीमा के भीतर है।’

2018019 लगातार दूसरा साल है, जब नरेंद्र मोदी सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूकी है। वित्त वर्ष 2017-19 में राजकोषीय घाटा पुनरीक्षित कर जीडीपी का 3.5 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि बजट अनुमान 3.2 प्रतिशत रहने का था। इसकी वजह वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से बाद पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों को बताया गया था।

डेलॉयट इंडिया की वरिष्ठ निदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री ऋचा गुप्ता ने कहा, ‘2019 के अंतरिम बजट ने राजकोषीय समेकन की राह एक बार फिर लंबी कर दी है। राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत से बदलकर 3.4 प्रतिशत किया जाना अहम नहीं है, जैसा कि उम्मीद की

बढ़ रहा ब्याज भुगतान और सब्सिडी

साल	सब्सिडी (लाख करोड़ रुपये)	ब्याज भुगतान (लाख करोड़ रुपये)	जीडीपी % के तौर पर सब्सिडी	जीडीपी % के तौर पर ब्याज भुगतान
2014-15	2.49	4.02	2.0	3.2
2015-16	2.64	4.42	1.9	3.2
2016-17	2.35	4.81	1.5	3.2
2017-18	2.24	5.29	1.3	3.2
2018-19*	2.99	5.88	1.6	3.1
2019-20**	3.34	6.65	1.6	3.2

स्रोत: केंद्रीय बजटनोट: 2019-20 के दौरान नोमिनल जीडीपी में 11 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान *संशोधित अनुमान **बजटीय अनुमान

से राजस्व, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपभोग शुल्क से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं, बढ़कर 41,519 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट दस्तावेजों से पता चलता है कि केंद्र सरकार अब उम्मीद कर रही है कि इस माध्यम से वित्त वर्ष 19 के पुनरीक्षित अनुमान में 41,519 करोड़ रुपये आएंगे, जो 48,661 करोड़ रुपये लक्ष्य की तुलना में कम है। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2018 तक गैर कर राजस्व संग्रह 1.38 लाख करोड़ रुपये या 2.45 लाख करोड़ रुपये बजट लक्ष्य की तुलना में 56.6 प्रतिशत था। वहीं दूसरी ओर गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी के 0.49 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 19 के बराबर ही है। यह वित्त वर्ष 2017-18 के 0.68 प्रतिशत की तुलना में कम है। इसके तहत केंद्र सरकार को उम्मीद है कि विनिवेश से 90,000 करोड़

रुपये जुटाए जाएंगे।

बहरहाल इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये विनिवेश लक्ष्य रखा है और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इससे लक्ष्य का 44 प्रतिशत यानी 35,532 करोड़ रुपये जुटाए जा सके हैं। यह भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई), ईटीएफ और कुछ बाईबैक के माध्यम से जुटाया गया है। वित्त वर्ष 2018 में कुल विनिवेश आय बजट के 72,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई थी।

अंतरिम बजट में कहा गया है कि चुनिंदा सीपीएसई में सरकार की इक्विटी के विनिवेश की राशि को नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में रखा जाएगा। वित्त वर्ष 2020 में इसका इस्तेमाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भारतीय रेलवे में निवेश करने के लिए होगा।

जीएसटी का लक्ष्य मामूली बढ़ा



कर संग्रह

इस साल जीएसटी संग्रह में कमी की संभावना को देखते हुए इसका लक्ष्य मामूली बढ़ा

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की अनुमानित गिरावट की वजह से केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्व संग्रह का लक्ष्य परंपरागत रखने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं सरकार ने जीएसटी संग्रह की कमी की भरपाई के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

बजट दस्तावेजों के मुताबिक सरकार जीएसटी से 7.61 लाख करोड़ रुपये संग्रह का अनुमान लगा रही है, जो चालू वित्त वर्ष के 6.44 लाख करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 18 प्रतिशत ज्यादा है। बहरहाल यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 19 के लिए रखे गए 7.43 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में महज 18,000 करोड़ रुपये ज्यादा है।

वहीं दूसरी तरफ प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेशन कर शामिल होता है, का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में



बदलाव की कोशिश

■ **सरकार ने प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य वित्त वर्ष 2020 में 15 प्रतिशत बढ़ाकर 13.80 लाख करोड़ रुपये किया**

50,000 करोड़ रुपये बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पहले 11.5 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020 के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 15 प्रतिशत बढ़ाकर 13.80 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह (अप्रैल-दिसंबर) 8.74

लाख करोड़ रुपये रहा है।

जीएसटी से कर संग्रह में मामूली सुधार का लक्ष्य रखने के बाद संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस बात के लिए सराहना की जा सकती है कि सरकार ने जीएसटी परिषद की बैठक कर 100 से ज्यादा सामान पर जीएसटी दरें घटाई हैं। कुल मिलाकर हमने पहले की जीएसटी दरों की तुलना में दरें कम रखी हैं। हमने जीएसटी के पहले की तुलना में कर की दरें कम रखी हैं और राज्यों के खाते में 14 प्रतिशत जीएसटी विचलन की राशि दे रहे हैं। यह तीन साल में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि है, जो अप्रत्यक्ष कर संग्रह में पहले कभी नहीं हुआ।’

कर संग्रह में कमी का बचाव करते हुए गोयल ने कहा कि चालू साल में औसत मासिक संग्रह 97,100 करोड़ रुपये प्रति महीने रहा है, जो पहले साल में औसतन 89,700 करोड़ रुपये था। केंद्र व राज्यों का कुल जीएसटी संग्रह चालू वित्त वर्ष में (अप्रैल-जनवरी) 9.71 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 13.48 लाख करोड़ रुपये रखा गया था।

गैर कर राजस्व से आएंगे 2.72 लाख करोड़ रुपये



गैर कर राजस्व

केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक से कर रही है 28,000 करोड़ रुपये लाभांश की उम्मीद

अंतरिम बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में 11.2 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ इससे 2.72 लाख करोड़ रुपये सरकारी खजाने में आने का अनुमान है। गैर कर राजस्व लक्ष्य वित्त वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमान में 2.45 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 19 में गैर करकर राजस्व में 27.3 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश कम मिलने और संचार सेवाओं की प्रक्रिया से कम आमदनी के बावजूद सरकार वित्त वर्ष 19 में अपना गैर कर राजस्व बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से 28,000 करोड़ रुपये अंतरिम लाभांश मिलेगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट अनुमान में विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपये कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2019 में 80,000 करोड़ रुपये था। केंद्र सरकार को उम्मीद है किइससे कम धन आने की चिंताओं के बावजूद विनिवेश से धन जुटा लिया जाएगा।

कुल मिलाकर केंद्र सरकार का गैर कर राजस्व वित्त वर्ष 2020 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.3 प्रतिशत रहेगा, जो वित्त वर्ष 2019 के स्तर के बराबर ही है। बहरहाल यह 2015-16 में जीडीपी का 1.82 प्रतिशत था, जिसकी तुलना में लक्ष्य कम है। रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश/अधिशेष वित्त वर्ष 2020 में बढ़कर 82,911 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है,जो वित्त वर्ष 2019 के पुनरीक्षित अनुमान 74,140 करोड़ रुपये की तुलना में ज्यादा है। वित्त वर्ष 2019 में केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 54,817 करोड़ रुपये का संग्रह होगा, जो बजट अनुमान की तुलना में 19,323 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसकी तुलना में देखें तो सरकारी उपक्रमों और अन्य निवेशों से लाभांश घटकर वित्त वर्ष 19 के बजट अनुमान के 52,494 करोड़ रुपये की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 45,124 करोड़ रुपये रह गया। सरकार ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020 में यह बढ़कर 53,159 करोड़ रुपये हो जाएगा। वित्त वर्ष 2020 में अन्य संचार सेवाओं

सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण गरीबों पर जोर



सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने और वंचित वर्गों के लिए कई घोषणाएं कीं। आयुष्मान भारत का बजट 166 प्रतिशत बढ़ा

आम चुनावों से पहले समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुआई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अपने अंतरिम बजट में सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और वंचित वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए अगले दस साल का खाका सामने रखा। उन्होंने कहा, ‘इस व्यापक दृष्टि के साथ हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बात होगी। भारत एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी से चलने वाला, ऊंची विकास दर, समतामूलक और पारदर्शी समाज होगा।’ अंतरिम बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन में पिछले साल के मुकाबले 7.5 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी की गई है लेकिन साथ ही कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है और कई योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का आवंटन

पिछले साल के मुकाबले 166 फीसदी बढ़ाकर 6,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत वेलनेस सेंटर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। 2018-19 में संशोधित अनुमानों में यह राशि 199.96 करोड़ रुपये है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आवंटन में भारी बढ़ोतरी की 1सदी बढ़ाकर

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन में पिछले साल के मुकाबले 7.5 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी

6,556 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क संपर्क के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी अधिक है। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के आवंटन में पिछले साल के मुकाबले

50 फीसदी बढ़ाकर 8,201 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 831 करोड़ रुपये मुखर्जी रूरबन मिशन को अंतरिम बजट में 800 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है जो पिछले साल के मुकाबले 77 फीसदी अधिक है। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी।

अलबत्ता कई अहम योजनाओं के आवंटन में कटौती की गई है। सरकार की स्वच्छ भारत योजना के आवंटन को घटाकर 12,750 करोड़ रुपये किया गया है जबकि पिछले साल के संशोधित अनुमान में यह 16,750 करोड़ रुपये था। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के बजट में भी 38 फीसदी कटौती की गई है। इसके लिए बजट में 4,066 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत सरकार ने मार्च 2019 तक बिजली से वंचित 18,000 गांवों को

▶ बजट प्रभाव

अचल संपत्ति की बिक्री से मिलने वाले पूंजीगत लाभ को दो आवासीय संपत्तियों में निवेश करने पर कर में छूट का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे पूंजीगत लाभ को एक साल के भीतर कर ही आवास में निवेश करने की सुविधा थी। इसके साथ ही अब किराये से होने वाले पूंजीगत लाभ 2.40 लाख रुपये तक की आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।



“सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है। छोटे और मझोले उद्यमियों को राहत देने का कदम भी स्वागतयोग्य है। बजट घोषणाओं से खपत बढ़ेगी और एफएमसीजी कंपनियों को फायदा होगा।”

चुनावी साल में मध्य वर्ग पर मेहरबान सरकार



मध्य वर्ग

5 लाख रुपये तक की आय पर कर से छूट, मानक कटौती में बढ़ोतरी का भी मिलेगा लाभ

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए मध्य वर्ग के लोगों की जेब में कुछ अतिरिक्त पैसे डालने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने जमाधारकों के जीवन को भी सहज बनाने की कोशिश की है।

कर लाभ का विस्तार : वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम का धारा 37ए में बदलाव किया है। यह धारा कर में कटौती से संबंधित है। अंतरिम बजट प्रस्ताव में कर धूलूत का लाभ 2.5 लाख रुपये से सासालाना आय से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को 6.5 लाख से अधिक आय पर कर नहीं देना पड़ेगा। धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर धूलूत की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इसके साथ ही चिकित्सा व्यय, बीबीमा लाभ पर भी पहले की तरह धूलूत का लाभ मिलेगा।

संक्षेप में कहें तो पहले कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये थी। ऐसे में अगर आपको करयोग्य आय 3.5 लाख रुपये तक थी तो आपको 2,500 रुपये कर छूट मिलती थी। इस बजट में इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। क्लियर टैक्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी अर्चित गुप्ता ने कहा कि इसे इस

तब समझा जा सकता है कि पहले किसी की आय 5 लाख रुपये थी तो उसे सालाना 12,500 रुपये कर देना पड़ता था। लेकिन अब 5 लाख रुपये तक आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

हलांकि यहाँ यह ध्यान देना होगा कि यह छूट 5 लाख रुपये की कार्यवायि आय पर ही उपलब्ध है। ऐसे में अगर किसी की आय 5 लाख रुपये से थोड़ा भी ज्यादा हो (100 रुपये भी अधिक हो) तो उसे मौजूदा कर स्लैब के हिसाब से पूरा कर देना होगा।

पीछेव्यूसी ईडिया में पार्टनर एवं लीडर पर्सनल टैक्स कुलदीन कुमार ने कहा, '5 लाख रुपये तक आय वाले लोगों को ही कर नहीं देना होगा लेकिन बाकी करदाताओं को पहले के स्लैब के हिसाब से ही कर का भुगतान करना होगा, क्योंकि कर रियायत धरा 87ए के तहत बढ़ाकर 1.2500 रुपये की गई है।'

A black and white photograph of a man and a woman working together at a desk. The man, on the left, has a beard and is wearing a denim shirt over a white t-shirt. He is looking at a laptop screen. The woman, on the right, has long dark hair and is wearing glasses and a light-colored button-down shirt. She is holding a clipboard and looking at the laptop screen. On the desk, there is a laptop, a white mug, and a glass of milk. In the background, there is a window with blinds and a door with a window.

5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले मध्य वर्ग के लोगों के पास अब खर्च करने के लिए पहले से बचेंगे ज्यादा पैसे

को मानक कटौती का लाभ मिलता है। इससे 30 फीसदी कर दायरे वालों को 3,000 रुपये और 20 फीसदी कर दायरे वालों को 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

व्याज आय पर टीडीएस सीमा में इजाफा : बैंक और डाकघरों में जमा पर मिलने वाले व्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। पहले

संपत्ति बेचने वालों को मिलेगा फायदा



रियल एस्टेट

करदाता एक मकान बेचकर उससे मिली रकम को दो मकानों में निवेश कर सकता है और पूंजी लाभ कर का फायदा उठा सकता है।

हैं। अगर विक्रता कोई मकान बना रहे हैं तो उसके पास ज्यादा समय होगा यानी उसे मकान विक्राने/उसके हस्तांतरण की तारीख से तीन साल के भीतर मकान का निर्माण पूरा करना होगा।

हालांकि इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति कई मकान बेचकर इनसे मिली-राशि को एक संघटित में निवेश करके धारा 54ए के तहत कर लाभ का फायदा ले सकता है या नहीं। कई कर अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई है लेकिन आय कर अपील पंचादों ने कदरदाताओं को धारा 54 के तहत कर लाभ लेने को अनुमति दी है क्योंकि यह एक लाभकारी प्रावधान है।

अधिकांश मामलों में आईटीएटी करदाताओं को उन मामलों में फायदा उठाने की अनुमति देते हैं जहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं होती है बशर्त उसने कानून के तहत बाकी सभी शर्तें पूरी की हों। टैक्समैनडॉट कॉम से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट नविका वाधवा कहते हैं, 'आईटीएटी की राय है कि आकलन अधिकारी अतिरिक्त शर्तें नहीं थोप सकता है।'

विवत मंत्री ने अंतरिम बजट में संपत्ति संबंधी करों को व्यावहारिक बनाकर सबसे अहम कदम उठाया है। अब कोई व्यक्ति यह घोषणा कर सकता है कि उसके पास खुद के इस्तेमाल के लिए दो घर हैं। साथ ही कोई इच्छुक एक मकान बेचकर उससे मिली रकम को दो मकानों में निवेश कर सकता है और दीर्घकालिक पूंजी लाभ को फायदा उठा सकता है। पहले यह फायदा केवल एक ही मकान के लिए मिलता था।

दीर्घकालिक पूजा लाभ कर का फायदा उठाने के लिए कुल पूजा लाभ दो करोड़ रुपये तक होना चाहिए। साथ ही यह दावा जीवन में केवल एक ही बार किया जा सकता है। कर कानूनों में बदलाव से उन परिवारों को फायदा होगा जो अपनी एक बड़ी संपत्ति बेचना चाहते हैं और

बच्चों के लिए दो अलग-अलग मकान लेना चाहते हैं। इससे मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा जहाँ संपत्ति की विलोपिता दर के दूसरे शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा है। आरक्षण पर एक्यूट कंसल्टिंग ग्रुप के संस्थापक सुरेश सुराणा ने कहा, 'कई बंगला मालिक भी इमारत बनाने के लिए अपना मकान डेवलपर को बेचते हैं। इसके बदले में डेवलपर उन्हें दो अपार्टमेंट देता है। ऐसे संपत्ति मालिकों को भी कर में फायदा होगा।'

कर लाभ पाने की दूसरी शर्त यथावत है।
मकान दो साल से भी अधिक समय तक आपके
कब्जे में रहना चाहिए। विक्रेता को मकान
बिकने/उसके हस्तांतरण की तारीख से एक साल
पहले या दो साल बाद मकान खरीदने की जरूरत

डेवलपर्स को मिल रही कर साहत बढ़ाई

पेरवल्ली क्षेत्र की सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ने किरायती आवासीय योजना विकसित करने का निर्णय लिया। रियल एस्टेट कंपनियों को आमेल रही कर रहत को अगले विवर्ष तक के लिए बढा दिया है। गोयल ने 2019-20 के अंतर्निम बजट में कहा कि व्यक्तितम करदाताओं को कुछ कर के मोर्चे पर कुछ रहत दी गई है। इसका प्रेरणालक्षित क्षेत्र पर सरकारतमक अमसर पड़ेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र को बढावा देने के लिए गोयल ने बिना बँके मकानों के अनुमानित किराये पर कर में छूट को एक साल से बढाकर दो साल करे का प्रस्ताव किये है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि घर खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम हो जाए। इसे स्थान में रखते हुये हमारे मकानों पर जीएसटी परिषद से एक मुंजी समूह गठित करने को कहा है, ताकि वह इस पर गौर करने के साथ-साथ इस बारे में जल्द-से-जल्द अपनी सिफारिशें पेश कर सके।

<p>बिज़नेस स्टैंडर्ड</p> <p>वर्ष 11 अंक 299</p>	
<p>कायम रहा अनुशासन!</p>	
<p>चुनाव पूर्व के बजट की दृष्टि से देखा जाए तो पीयूष गोयल का बजट बहुत बुरा नहीं है। वोट दिलाने वाली घोषणाओं पर करीब एक लाख करोड़ रुपये (अगले वर्ष के जीडीपी के एक फीसदी का करीब आधा) व्यय करने की घोषणा की गई है लेकिन राजकोषीय घाटा इस वर्ष के जीडीपी के 3.4 फीसदी के संशोधित आंकड़े से अपरिवर्तित रहेगा। राजकोषीय सुधार में ठहराव सहन किया जा सकता है। अगर इसमें नकारात्मक बदलाव आता तब जरूर गड़बड़ होती। अगर मूलभूत न्यूनतम आय जैसी अन्य घोषणाएं होतीं तब जरूर इसे नकारात्मक कहा जा सकता था।</p>	<p>इसके बावजूद अगर महत्वाकांक्षी संशोधित आंकड़े अमल में नहीं आए तो चालू वर्ष का घाटा बढ़ सकता है। खासतौर पर निगम कर राजस्व और विनिवेश प्रक्रिया के मामले में। सरकार के ऋण कार्यक्रम के आकार ने पहले ही बॉन्ड बाजार में ब्याज दरों को रोक रखा है जबकि सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात गिरने के बजाय बढ़ता जा रहा है।</p> <p>पांच वर्ष में सरकार ने कर-जीडीपी अनुपात को 2013-14 के 10.1 फीसदी से बढ़ाकर चालू वर्ष के संशोधित आंकड़ों में 11.9 फीसदी तक पहुंचा दिया है। यह उल्लेखनीय सुधार है। अगर आयकर चुकता करने वालों की तादाद</p>
<p>के हिसाब से देखा जाए तो कर अनुपालन में भी सुधार हुआ है। इस अवधि में राजकोषीय समायोजन 1.1 फीसदी रहा जो काफी बेहतर है। प्रार्थमिक घाटा नाम मात्र का है। ऐसे में पूरा घाटा अतीत की गलतियों का परिणाम है। परंतु 3 फीसदी का लक्ष्य शाश्वत है। अगले वर्ष राज्यों के साथ संसाधन साझा करने की वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो सकता है। हकीकत में मौजूदा वर्ष के आंकड़ों को राज्यों को अनुमानित हस्तांतरण में कमी से भी समर्थन मिला है।</p> <p>चुनावी घोषणाओं की बात करें तो सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आय समर्थन के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है। इसके बचाव में कहा जा रहा है कि यह कृषि उपज के मूल्य में कमी की भरपाई करेंगी। यानी यह एक तरह से कारोबारी नुकसान के हजने के रूप में दी जाने वाली राशि है। बात तार्किक है लेकिन अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों के पास इतनी उपज नहीं होती कि वे उसे मंडी में बेच सकें। सच</p>	<p>तो यही है कि सरकार का यह कदम न्यूनतम लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में ही एक कदम है। यह एक राजनीतिक कदम है और राज्यों द्वारा की गई ऐसी ही अन्य घोषणाओं को देखते हुए किया गया है। केंद्र सरकार राजनीतिक श्रेय चाहती है।</p> <p>दूसरी कल्याण योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन की योजना है जहां सरकार आधी लागत चुकाएगी। यह योजना तमाम अन्य खुली कल्याणकारी योजनाओं की तरह भविष्य में बोझ बन सकती है। अमीर देशों में भी ऐसा देखने को मिल चुका है। आयुष्मान भारत की बात करें तो यह यकीन करना मुश्किल है कि 6,000 करोड़ रुपये का बजट दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए पर्याप्त होगा। राज्यों के योगदान देने के बावजूद और अगर एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कम से कम कुछ बार अस्पताल होने की जरूरत पड़े तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 50 करोड़ की बीमित आबादी में से करीब 1.5 करोड़ लोगों को हर साल इलाज की जरूरत</p>
<p>पड़ेगी। ऐसे में यह मानना उचित होगा कि 50 करोड़ की बीमित आबादी का करीब दो फीसदी हर वर्ष अस्पताल में भर्ती हों। संयुक्त रूप से 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले साल कवरज बहुत कम होगा या अस्पताल में भर्ती होने की औसत लागत करीब 6,000 रुपये होगी। यह कितना वास्तविक है ?</p> <p>निहायत असमानता भरे समाज में गरीबों या वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण पर किए जाने वाले खर्च के खिलाफ दलील देना काफी मुश्किल है। खासतौर पर तब जबकि मध्य वर्ग के लिए निरंतर कर संबंधी राहत की घोषणा की जा रही हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कल्याण योजनाओं पर इस खर्च के लिए राजकोषीय गुंजाइश मौजूदा कार्यक्रमों की फंडिंग कम करके ही तैयार की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अगले वर्ष के आवंटन में इस वर्ष की तुलना में कमी की गई है। इसके अलावा इसमें उज्ज्वला (गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन),</p>	<p>कर्मचारी पेंशन योजना, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना, अन्य वंचित समूहों के लिए ऐसी ही योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, श्वेत क्रांति, पोषण आधारित सब्सिडी आदि शामिल हैं। अन्य आवंटन चालू वर्ष के बजट आवंटन से कम हैं। इनमें हरित क्रांति, नीली (मत्स्य) क्रांति, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और शहरी मिशन आदि। शायद सरकार का दावा 2.5 लाख रुपये के बजट आवंटन से कम करके 3.50 लाख रुपये किया जा सकता था। आखिरी बार 2014 में करमुक्त को समझ सके। 2.5 लाख रुपये तय किया गया था। परंतु ऐसा करने से शायद लोकसभा में मोदी मोदी के नारों के बीच मेज थपथपाने का सिलसिला वैसा न चलता जैसा कि देखने को मिला।</p>



अजय मोहंती

3.5 और 7.5 फीसदी के फेर में फंसी अर्थव्यवस्था

राजनीतिक गलियारों में यह महसूस किया जाने लगा है कि तेज विकास से रोजगार नहीं पैदा होंगे। इसलिए राजनेता लोकलुभावन योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं जो बड़ा खतरा है। बता रहे हैं टी टी राम मोहन

इस अंतरिम बजट पर आम चुनाव की छाप साफ महसूस की जा सकती है। यकीनन इसमें सबसे बड़ा ऐलान किसानों के लिए नकद हस्तांतरण योजना का है, जिस पर 75,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही, समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए 5 फीसदी के ब्याज अनुदान का ऐलान भी किया गया है।

इसके अलावा, सरकार मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए भी हरसंभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में अब 5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होगा। वहीं, अब नौकरपेशा कर्मचारियों के लिए मानक कटौती भी अब 50,000 रुपये कर दी गई है। सिर्फ इन दो प्रस्तावों से सरकारी खजाने पर 23,200 करोड़ रुपये की चपत लगने वाली है।

कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक के बजाय दो रिहाइशी मकानों के लिए पूंजीगत लाभ को रोलओवर करने की सुविधा मिलेगी। वहीं, अब नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी हिस्सेदारी भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने 3,000 रुपये मासिक पेंशन का वादा भी किया है।

सरकार की नकद हस्तांतरण योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। वहीं, आयकर में छूट का फायदा 3 करोड़ करदाताओं को मिलेगा। जाहिर है,

चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोशिश छोड़ी नहीं है। तो सवाल उठता है कि सरकार को इन नेमतों और ऐलानों का राजकोषीय स्थिति पर क्या असर पड़ेगा ? दो दिनों पहले जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों को बजट के साथ मिलाकर देखें तो बड़ी विरोधाभासी बातें नजर आती हैं। बजट अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 फीसदी रह सकती है। वहीं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए संशोधित आंकड़ों की मानें तो चालू वित्त वर्ष में करीब 6 फीसदी वृद्धि दर रह सकती है! सरकार की मानें तो बजट में 11.5 फीसदी के मामूली इजाफे से अर्थव्यवस्था में 8 फीसदी की रफ्तार आ जाएगी। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि राजकोषीय घाटे की हालत क्या रहेगी।

वैसे भी अगले वित्त वर्ष में खर्चों पर लगाम लगाए बिना राजकोषीय घाटे को जीडीपी की तुलना में 3.4 फीसदी की सीमा में बांधे रखना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। सरकार मानकर चल रही है कि इस वित्त वर्ष में कर्ों से होने वाली कुल कमाई बजट अनुमान के बराबर ही रहेगी, जबकि यह स्पष्ट है कि कुल कर राजस्व अब तक लक्ष्य से कम रहा है। इसी एक अनुमान की वजह से वित्त मंत्री को बजट अनुमानों के

के हिसाब से देखा जाए तो कर अनुपालन में भी सुधार हुआ है। इस अवधि में राजकोषीय समायोजन 1.1 फीसदी रहा जो काफी बेहतर है। प्रार्थमिक घाटा नाम मात्र का है। ऐसे में पूरा घाटा अतीत की गलतियों का परिणाम है। परंतु 3 फीसदी का लक्ष्य शाश्वत है। अगले वर्ष राज्यों के साथ संसाधन साझा करने की वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो सकता है। हकीकत में मौजूदा वर्ष के आंकड़ों को राज्यों को अनुमानित हस्तांतरण में कमी से भी समर्थन मिला है।

चुनावी घोषणाओं की बात करें तो सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आय समर्थन के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है। इसके बचाव में कहा जा रहा है कि यह कृषि उपज के मूल्य में कमी की भरपाई करेंगी। यानी यह एक तरह से कारोबारी नुकसान के हजने के रूप में दी जाने वाली राशि है। बात तार्किक है लेकिन अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों के पास इतनी उपज नहीं होती कि वे उसे मंडी में बेच सकें। सच

इन लक्ष्यों की अहमियत ही खत्म हो जाती है। इस बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने एफआरबीएम पर 2016-17 की अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया है। सीएजी ने इस बारे में सरकार से बजट से अलग वित्तीय प्रबंधनों का पूरा ब्योरा देने के लिए कहा था। इसके बाद ही हम राजकोषीय घाटे की असल स्थिति जान पाएंगे और फिर एक तर्कसंगत लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे।

जीडीपी की तुलना में कर्ों का बढ़ता अनुपात और कम होते खर्च भी सरकारी खजाने की सेहत के लिए काफी जरूरी हैं। चालू वित्त वर्ष के बजट में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया था। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की तुलना में कर्ों का अनुपात करीब 12.1 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि इससे पहले 2010-15 में यह 10.2 फीसदी रहा था। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में यह 12.4 और 2020-21 में 12.7 फीसदी रहने की उम्मीद जताई थी। हालांकि, इस बजट ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके मुताबिक 2018-19 में कर-जीडीपी का अनुपात 11.9 फीसदी रहेगा, जबकि अगले दो वित्त वर्षों में यह 12.1 फीसदी के आंकड़े पर स्थिर रहेगा।

हालांकि, सबसे बुरी खबर तो व्यय के मामले में आ रही है। घरेलू उत्पाद की तुलना में सरकार का कुल खर्च 2010-15 के 14.3 फीसदी के मुकाबले इस साल घटकर 13 फीसदी तक आ गया था। लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसके 13.3 फीसदी के स्तर तक चढ़ने की संभावना है। यह तो बस शुरुआत है। किसानों के लिए नकदी हस्तांतरण योजना का खर्च आने वाले वर्षों में बढ़ता जाएगा। साथ ही, आने वाले वर्षों में सब्सिडी में भी किसी प्रकार की गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिन पर सरकार सब वक्त जीडीपी का 1.4 फीसदी खर्च करती है।

राजकोषीय घाटे में अगर गिरावट आती है, तो समझा जाता है कि निजी निवेश बढ़ रहा है और इससे विकास की उम्मीदें को पर मिलते हैं। हालांकि, अब इन संभावनाओं पर संदेह के काले बादल मंडराने लगे हैं। दोहरी बैलेंस शीट की समस्या के निपटारे में देरी का खमियाजा अब निजी निवेश के आंकड़ों पर दिखने लगा है। चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित बजट आंकड़ों में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में पूंजी निवेश के वास्ते अतिरिक्त आवंटन का कोई जिक्र नहीं है और नए वित्त वर्ष में तो इसके लिए कोई आवंटन ही नहीं किया गया है।

राजनीतिक गलियारों में यह बात घर करने लगी है कि तेज विकास से रोजगार नहीं पैदा होंगे और इसीलिए राजनेता अब लोकलुभावन और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। यह सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से देश के लिए कम से कम निकट भविष्य में 3.5 फीसदी के राजकोषीय घाटे और 7.5 फीसदी की विकास दर का कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा।

(लेखक आईआईएम, अहमदाबाद में प्राध्यापक हैं)

अंतरिम बजट विश्लेषण 2019-20 7

अंतरिम बजट 2019-20 के अंतर्गत सरकार द्वारा पेश किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण।

अंतरिम बजट 2019-20 के अंतर्गत सरकार द्वारा पेश किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण।

अंतरिम बजट 2019-20 के अंतर्गत सरकार द्वारा पेश किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण।

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का मंत्र



सिराज चौधरी

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

देश की कृषि अर्थव्यवस्था की सफलता का फॉर्मूला बहुत आसान है। किसान उतनी ही जमीन से कम लागत में अधिक उत्पादन करने में समर्थ होने चाहिए। उनके जोखिम को कम किया जाए और उन्हें बाजार से जोड़

राजकोषीय नीति के समक्ष आसन्न दोहरा संकट



अजय शाह

अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है और यह सही समय है कि हम अपेक्षाकृत व्यापक फलक को लेकर बात करें। बजट प्रक्रिया और राजकोषीय नीति के सामने अब दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का गलत आकलन और उसका अधिमूल्यित अनुमान। इस बात के कर लक्ष्य और बॉन्ड जारी करने के कार्यक्रम पर कहीं गहरे प्रभाव पड़ेंगे। दूसरा, लोकलुभावन पात्रता कार्यक्रम। इनका दुनिया भर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत को भी इसके राजनीतिक निहितार्थ के प्रबंधन के लिए काम करना होगा।

अंतरिम बजट अप्रैल-जून तिमाही से प्रभावी होगा और जुलाई में सरकार बदलने के बाद पुनः बजट पेश किया जाएगा जो वर्ष भर के लिए

सरकार की नीति तय करेगा। बहरहाल, यह बजट अवसर देता है कि हम ठहरकर देश की बजट प्रक्रिया और राजकोषीय नीति की चुनौतियों पर विचार करें।

पहला सवाल जीडीपी के आंकड़ों से जुड़ा है। सबको पता है कि देश के आधिकारिक आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं। यह केवल अर्थशास्त्रियों की रुचि का मामला है। बहरहाल, जीडीपी आंकड़ों का बजट निर्माण पर सीधा असर होता है।

हर बजट प्रक्रिया में जीडीपी के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। इसमें 0.08 फीसदी का गुणाकर उसे व्यापक कर नौकरशाही का लक्ष्य बनाया जाता है। जीडीपी आंकड़ों में चूक से कर लक्ष्य में चूक उत्पन्न होती है। वर्ष 2018-19 का कर राजस्व जीडीपी का 7.9 फीसदी था जो 2019-20 के लिए 8.1 फीसदी है।

हमारे यहां यह बात लगभग स्वीकार्य है कि जीडीपी के अनुमान लगाने में चूक होती है। कुछ स्वतंत्र आंकड़ों के स्रोत कॉर्पोरेट बिक्री, कॉर्पोरेट मुनाफा, निजी निवेश आदि बताते हैं कि आधिकारिक अनुमान बढ़ाचढ़ाकर किए गए हैं। उदाहरण के लिए 2014-15 से 2017-18 तक नॉमिनल जीडीपी 37 फीसदी बढ़ी। परंतु 5019 गैर तेल गैर वित्त कंपनियों की नॉमिनल शुद्ध बिक्री 22 फीसदी बढ़ी।

अगर जीडीपी बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत की गई



तो कर लक्ष्य ऊंचे होंगे। तब कर निरीक्षक भी दबाव बढ़ाते हैं और अनावश्यक तनाव उत्पन्न होता है।

वर्ष 2014-15 में शुद्ध कर राजस्व 9.8 लाख करोड़ रुपये था जिसके जीडीपी का 7.5 फीसदी होने का अनुमान था। पांच वर्ष बाद यह 17.1 लाख करोड़ रुपये और जीडीपी का 8.1 फीसदी अनुमानित है। या नॉमिनल जीडीपी इन पांच वर्षों में 62 फीसदी बढ़ा जैसा कि बजट निर्माण में अनुमान लगाया गया था।

बॉन्ड कार्यक्रम को लेकर बजट आकलन भी जीडीपी के गलत आकलन से प्रभावित होता है।

^[1] अंतरिम बजट 2019-20 के अंतर्गत सरकार द्वारा पेश किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण



हम विशेष रूप से केंद्र सरकार प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान योजना- छोटे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लेकर आशावादी हैं। हालांकि किसानों के लिए और बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह अच्छा कदम है, जो किसानों को बाजार के अनुरूप बनने में मदद करेगा। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए मॉडल एपीएमसी अधिनियम, आवश्यक ज़िंस अधिनियम को लागू करने जैसे बाजार सुधारों की पहल करने की जरूरत है। पशुपालन और मत्स्यपालन से जुड़े किसानों को ब्याज में कुल 5 फीसदी छूट एक सकारात्मक कदम है, जिसका किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा मनरेगा के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये किए जाने से ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे में इजाफा होगा। कर सुधारों के जरिये किसानों और उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आने से अर्थव्यवस्था की वृद्धि को और बढ़ावा मिलेगा।

बजट घोषणा उद्योग के लिए सकारात्मक नजर आ रही है। इस अंतरिम बजट में देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर और जोर दिया गया है।रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जलमार्ग की बढ़ोतरी पर जोर दिया जा रहा है। रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये संपर्क में सुधार और सागर माला परियोजना को बढ़ाने के लिए बजट आवंटन देश में इस्पात की ज्यादा ख़पत के संकेत हैं।

अनिल कुमार चौधरी

चेयरमैन, सेल

8 अंतरिम बजट और जिंस 2019-20



गोल्ड एक्सचेंज

सरकार व्यापक स्वर्ण नीति के तहत स्वर्ण हाजिर एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव पर कर रही विचार

स्वर्ण मुद्र्रीकरण में बदलाव पर विचार

वर्ष 2018–19 के बजट प्रस्ताव लागू करने से संबद्ध एक दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार व्यापक स्वर्ण नीति के तहत स्वर्ण हाजिर एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि स्वर्ण मुद्र्रीकरण योजना में संशोधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और इन पर विचार-विमर्श चल रहा है।

हालांकि नई व्यापक स्वर्ण नीति पर लंबे समय से विचार-विमर्श चल रहा है, लेकिन सरकार ने पहली बार औपचारिक तौर पर कहा है कि स्वर्ण मुद्र्रीकरण योजना को संशोधित किया जा रहा है। इस योजना की घोषणा नवंबर 2015 में हुई थी, जिसका मकसद भारतीय परिवारों के पास अनुपयोगी पड़े सोने को एकत्रित करना था। यह योजना अब तक नाकाम साबित हुई है, जिसमें मुश्किल से 20 टन से कम सोना जुटाया जा सका है।

वित्त मंत्रालय योजना को संशोधित करने के बारे में पिछले कई महीनों से विचार-विमर्श कर रहा है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। अंतरिम बजट के प्रस्तावों को लेकर लेकर सराफों का सकारात्मक रुख है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इससे सोने की मांग में इजाफा होगा।

दस्तावेज में कहा गया है, ‘सोने को एक वित्तीय आस्ति के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक प्रारूप नीति संबंधित मंत्रालयों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेज दी गई



अंतरिम बजट के प्रस्तावों को लेकर लेकर सराफों का सकारात्मक रुख है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इससे सोने की मांग में इजाफा होगा

हैं और गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श चल रहा है। स्वर्ण मुद्र्रीकरण योजना में संशोधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और इन पर विचार-विमर्श चल रहा है।' सरकार के 2019 के केंद्रीय बजट में

साफ तौर पर कहा गया है कि सोने को एक वित्तीय आस्ति बनाने के लिए व्यापक स्वर्ण नीति विभिन्न मंत्रालयों को उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए भेज दी गई है। गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने को लेकर भी विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार ने स्वर्ण मुद्र्रीकरण योजना में भी संशोधन किया है और इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा, ‘किसानों और मध्य वर्ग के हाथों में ज्यादा खर्च योग्य आय आने से सोने की खपत बढ़ेगी।' उन्होंने किसानों को नकद हस्तांतरण समेत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने के उन कई उपायों के बारे में बात की, जो ग्रामीण आमदनी बढ़ाएंगे और इस आय का एक हिस्सा सोने की खरीदारी पर खर्च होगा। पीएनजी ज्वैलर्स के सीएमडी सौरभ गाडगिल ने कहा, ‘यह बजट संकेत देता है कि यह रत्नाभूषण उद्योग को साफ-सुथरा और संगठित बनाने का उचित समय है। इसके लिए एक व्यापक स्वर्ण नीति लाई जाएगी ताकि सोने को एक आस्ति वर्ग बनाया जा सकेगा। स्वर्ण हाजिर एक्सचेंज, स्वर्ण जमा खाता, स्वर्ण मुद्र्रीकरण योजना के लिए शुरुआती दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह बजट अर्थव्यवस्था में आवश्यक आत्मविश्वास लेकर आएगा और उद्योग को लंबी अवधि में फायदा पहुंचाएगा।'



टायर उद्योग

भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन है काफी कम और उत्तर-पूर्व में उद्योग की मांग पूरी करने की है बहुत संभावना

बजट में टायर क्षेत्र के लिए विकास के अवसर : विनिर्माता

ऑटोमोटिव टायर मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटमा) के चेयरमैन अनंत गोयनका ने कहा कि यह विकासोन्मुख बजट है जिसमें बुनियादी संरचना पर काफी ध्यान दिया गया है और इसमें टायर क्षेत्र के लिए भी विकास के अवसर हैं। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 19,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पहले ही ग्रामीण सड़कों का निर्माण तीन गुना हो चुका है। अगले पांच वर्षों में भारत पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। इसलिए जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है देश को सड़कों, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डों, शहरी परिवहन आदि के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। वास्तव में भारत दुनिया में सबसे तेजी से राजमार्गों का विकास करने वाला देश है। प्रतिदिन 27 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण पर इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। परिवहन और विकास का एक अभिन्न अंग होने की वजह से टायर इस विकास गाथा का लाभार्थी भी होगा और संचालक भी।

टायर उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक रहने वाला बजट का एक अन्य पहलू उत्तर-पूर्व में बढ़ता संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन काफी कम है और उत्तर-पूर्व में उद्योग की मांगें पूरी करने की बहुत संभावना है। अलबत्ता उत्तर-पूर्व से रबर



अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए किया गया है 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन

की कुशलतापूर्वक ढुलाई करके उसे देश के उपभोग करने वाले अन्य भागों तक पहुंचाना एक मसला रहा है। उत्तर पूर्व में संरचनात्मक विकास के लिए आवंटन बढ़ने से निश्चित तौर पर इसमें मदद मिलेगी।

उलट शुल्क संरचना भारतीय टायर उद्योग के लिए एक बड़ी बाधा रही है। पिछले कुछेक सालों में सरकार द्वारा इस संबंध में आंशिक रूप से मददगार कदम उठाए गए हैं। उद्योग को आगे और राहत मिलने की उम्मीद थी। उद्योग का मानना ​​है कि उलट शुल्क संरचना जैसी विनिर्माण विरोधी नीतियों पर भविष्य में पूरा ध्यान दिया जाएगा।

किसानों के साथ किया गया कपट



आहत

किसानों का कहना है कि किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया गया है

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जित कुमार शर्मा उर्फ कक्काजी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'यह कष्टपूर्ण बजट है। सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये देने की गारंटी बात करी है। मैं कहता हूँ अगर सरकार किसानों को 6,000 रुपये देने की गारंटी नहीं देती तो उल्टा किसान उन्हीं 6,000 रुपये देने को तैयार हो जायेंगे। यह किसान विरोधी बजट है। हमारे कृषि उपकरणों, बीबीजों, उर्वरकों तक पर 18 से 28 प्रतिशत की जीएसटी लगा दिया है। ट्रेडर के दाम 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। ट्रेडर

गए हैं। यूरिया की बोरी का आकार पांच किलो कम करके उसकी कीमत बढ़ा दिया है। साफ जलही है सरकार का 100 रुपये लूटकर किसानों को 10 रुपये पकड़ा रही है।' महाराष्ट्र के सलेगांव सिद्धि में अन्ना हजारे के राशन अनशन पर मौजूद एक कक्काजी ने कहा कि इस किसान विरोधी बजट को देखकर उन्हें 100 फीसदी आशंका हो गई है कि सरकार किसानों में वीरगम अर्पणों को फिक्स कर रखने के बजाय ऐसे नहीं होता तो वह हारती। अगर ऐसा नहीं होता तो वह हारती। किसानों को ऋण मुक्ति का उपाय करके बजाय उनके साथ ऐसा मजाक नहीं करती।

किसानों को हल्की राहत, और की दरकार



कृषि

किसानों ने बजट की घोषणाओं को कम बताया, उन्हें ज्यादा राहत मिलने की आस थी

मोदी सरकार ने चुनावी साल में पेश किया एक अंतरिम बजट में किसानों को तुलना के लिए कई घोषणाएँ की हैं। लेकिन किसान इन्हें हल्की राहत बता रहे हैं जबकि उन्हें ज्यादा मिलने की आस थी। बजट में दो हेक्टेयर जोत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये पशुपालक और मत्स्य पालक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) का विस्तार और व्याज छूट के साथित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए

भी व्याज सहायता की घोषणा की गई है। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने दो क्लेयर खेती पर सालाना 6,000 रुपये की सहायता की ऊँट के मुँह में जिर के समान बताया है। वह सहायता तेलंगाना मॉडल के तहत दी जाने वाली सहायता से करीब सात गुना कम है। केसीसी का पशुपालन व मत्स्य पालन के लिए विस्तार से भी खास लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि अब भी कई किसान बिना बताये इन कामों में इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे।

भारत कृषक समाज के अध्यक्ष
अजयवीर जाखड़ कहते हैं कि
बजट में छोटे व सीमांत किसानों
को सालाना 6,000 रुपये की
आर्थिक सहायता अच्छा कदम है
लेकिन यह काफी नहीं है और इस
सहायता से बीते चार वर्षों में सरकार
की कृषि नीति से किसानों को हुए
नुकसान की भरपाई भी नहीं हो
सकती। केसीसी का पशुपालन और
मत्स्य पालन में भी विस्तार
है। लेकिन पशुपालन और मत्स्य
पालन को कृषि का दर्जा देकर
आयकर में छूट दी जानी चाहिए।
केसीसी का विस्तार कृषि उपकरणों
के लिए भी होना चाहिए। आपदा
के समय कृषि ऋण में व्याज छूट
अच्छा निर्णय है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि



किसान सम्मान योजना केवल किसान वोट पाने की योजना है। अगर सीधे सहायता राशि देनी है तो तेलंगाना राज्य की तर्ज पर दी जाय। उन्होंने कहा कि बजट में स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने, फसलों के समर्थन मूल्य पर 100 फीसदी खरीद, फसल बीमा योजना में प्रीमियम घटाने की उम्मीद पूरी न होने से किसान निराश हैं।

... कम मिली राहत

■ बजट में की गई है 2 हेक्टेयर जोत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने, पशुपालक और मत्स्य पालकों तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) का विस्तार करने की घोषणा

■ 6,000 रुपये की सहायता को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बता रहे किसान

■ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, फसलों के समर्थन मूल्य पर 100 फीसदी खरीद, फसल बीमा योजना में प्रीमियम घटाने की उम्मीद पूरी न होने से किसान निराश

गायों की उत्पादकता पर जोर



बढ़ेगा उत्पादन

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों की नस्ल सुधार के लिए योजना बनाने की घोषणा

अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों की नस्ल में सुधार के लिए एक योजना बनाने की घोषणा की है। इसके लिए एक अलग ब्रांड इकाई का गठन किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का हिस्सा होगी। इससे जुलाई २०१४ में शुरू किया गया था। इसका मकसद पेशेवर फार्म प्रबंधन और बेहतर पोषण के जरिये देसी नस्ल की गायों की उत्पादकता बढ़ाना है। गोयल ने कहा, 'मैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उत्पन्न करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आयोग गायों के लिए कानूनों और कल्याण

योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की भी देखभाल करेगा।' सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया है।

गाय भारतीयों के लिए एक पवित्र पशु है और दूध तथा दुग्ध उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी के जरिये दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निजी स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। मवेशियों के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी सहित कई अन्य उपयोगों के दम पर देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है।

गोयल ने कहा, 'गोमाता के सम्मान के लिए ये सरकार कभी पीछे नहीं



गोयल ने बजट में की है राष्ट्रीय
कामधेनु आयोग की स्थापना करने
की घोषणा

|||||

हेट्टी।' इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय किया है।



વસ્ત્ર ઉદ્યોગ

राज्य शुल्कों से राहत (आरओएसएल) के लिए आवंटन राशि में इजाफे से मिलेगी सहायता

विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य शुल्कों से राहत (आरओएसएल) के लिए आवंटित राशि बढ़ाने के सरकार के फैसले से कपड़ा क्षेत्र को बड़ावा मिलेगा। अंतरिम बजट 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आरओएसएल योजना में आवंटित राशि को 2,164 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,664 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस योजना की खातिर 1,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।

सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) के चेयरमैन केवी श्रीनिवासन ने कहा कि आरओएसएल योजना के लिए बजट आवंटन में इजाफा करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। हम सरकार से

आरओएसएल योजना के अंतर्गत सूती धागे और कपड़े को भी शामिल करने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा भी कपड़ा और वस्त्र उद्योग को किसान और उपभोक्ता केन्द्रित इस बजट से फायदा मिलने वाला है। आयकर छूट को सीमा बढ़ाने से निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को खर्च योग्य आमदनी बढ़ेगी जिसका एक हिस्सा कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र में आएगा।

क्लादिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमआई) के अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि बजट के प्रस्तावों से मध्य वर्ग और ग्रामीण भारत का उपभोग तथा उपभोक्ता व्यय बढ़ने की संभावना है और इस कारण कपड़ा और वस्त्र उद्योग को लाभ होगा।

